

**क्या आप व्योरी से  
पेशान है ?**

Digi Notes, smart shortcuts for smart students.



*Mahendra's*  
**Digi  
Notes**

**VERSION 2.0**

**सामान्य  
सचेतता**

**IBPS PO - 2017  
SPECIAL**

*Mahendra's*<sup>TM</sup>



[www.mahendras.org](http://www.mahendras.org)  
[www.mahendraguru.com](http://www.mahendraguru.com)

## विश्व खाद्य भारत समारोह – 2017

**स्थान :** विज्ञान भवन नई दिल्ली

**तिथि :** 3 नवंबर 2017

**उद्घाटन :** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आयोजक : केन्द्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व खाद्य समारोह का उद्देश्य खाद्य अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करना और वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य तथा सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करने के द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने के विजन को प्राप्त करना है।

पहली बार भारत ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ऐसे किसी समारोह की मेजबानी की है।

विश्व खाद्य भारत मंच एक वैश्विक खाद्य फैक्टरी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाएगा और यह देश द्वारा खाद्य सुरक्षा अर्जित किए जाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

भारत में अगले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दस बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किए जाने तथा दस लाख रोजगारों का सृजन किए जाने की उम्मीद है।

विश्व खाद्य क्षेत्र भारत समारोह में दो हजार से अधिक प्रतिभागियों, 30 देशों की 200 से अधिक कंपनियों, 18 मंत्रिस्तरीय तथा व्यवसाय शिष्टमंडल तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की सभी अग्रणी घरेलू कंपनियों के सीईओ समेत लगभग 50 वैश्विक सीईओ और भारत में 28 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।

**साझेदार देश :** जर्मनी, जापान एवं डेनमार्क विश्व खाद्य समारोह के साझेदार देश हैं।

**फोकस देश :** इटली और नीदरलैंड फोकस देश हैं।

उद्घाटन समारोह के अवसर पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ-साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी थे। वैश्विक एवं घरेलू क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के सीईओ आदि के अलावा कई देशों के मंत्रिस्तरीय शिष्टमंडल भी उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहें थे।

15 देशों के 200 से अधिक सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय एवं व्यवसाय शिष्टमंडल बी-टू-बी/बी-टू-जी बैठकों में भाग लिया।

इस विशाल समारोह में आठ क्षेत्रवार सम्मेलन, भारत के वित्त मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में 'भारत एक पसंदीदा गंतव्य' पर दो पूर्ण सत्रों का, भारत के खाद्य मानकों एवं सुरक्षा प्राधिकरण के सहयोग से 'एक राष्ट्र, एक खाद्य कानून- खाद्य क्षेत्र में निवेश के लिए एक सक्षमकारी नियामकीय वातावरण' का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त, 20 राज्य सत्रों एवं 6 देश सत्रों का भी आयोजन किया गया। समारोह के दौरान 7 क्षेत्रवार प्रकाशन भी जारी किए गए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का थीम पवेलियन उत्पादों, उत्पाद उपलब्धता का भू-मानचित्रण एवं मेगा फूड पार्कों के लिहाज से विश्व को भारत की प्रस्तुति का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस समारोह को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, विदेश मामले मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है।

### हरित पहल और रेलवे विद्युतीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे विद्युत अभियंता संस्था, (आईआरईई) भारत के माध्यम से आयोजित हरित पहल और रेलवे विद्युतीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

**सम्मेलन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:**

भारतीय रेलवे में उपलब्ध हरित ऊर्जा विकल्पों के बारे में भागीदारों में जागरूकता बढ़ाना

मौजूदा नीतियों और जोखिम कारकों का मूल्यांकन, सुधार का सुझाव देना और भावी अवसरों का पता लगाना  
सफल क्रियान्वयन के लिए रणनीति तैयार करना  
अन्य देशों और मानदण्डों के साथ तुलना करना  
सफल पायलट परियोजनाओं का अध्ययन करना  
भारतीय रेल की उच्च गति के इंजन आवश्यकताओं को पूरा करना  
भारतीय रेल में ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के लिए समाधान तलाशना  
'मेक इन इंडिया' को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए नई भारतीय रेलवे बनाने की पहल  
इस विजन के अनुरूप निम्नलिखित कार्ययोजना शुरू की जा रही है।

### रेल ट्रेकों का विद्युतीकरण

अभी 33000 मार्ग किलोमीटर ट्रेकों का बिजलीकरण किया गया है। 40 प्रतिशत रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हुआ है और इसमें 55 प्रतिशत सवारी गाड़ी और 65 प्रतिशत माल गाड़ी है। इनके मद में भारतीय रेल के कुल ईंधन बिल का केवल 35 प्रतिशत आता है। हम अब रेल का 100 प्रतिशत बिजलीकरण करने जा रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2021-22 तक फास्टट्रेक आधार पर 33,000 मार्ग किलोमीटर नेटवर्क का बिजलीकरण किया जाएगा। इससे ऊर्जा बिल 26,500 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर के घटकर 16,000 करोड़ रुपये हो जाएगा यानी 100 प्रतिशत संचालन के साथ प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। बिजलीकरण की गति तेज करने के लिए रेल मंत्रालय इरकॉन, राइट्स तथा पीजीसीआईएल जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को शामिल करेगा। बिजलीकरण की गति में तेजी आने से रेल का ईंधन बिल 10000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कम होगा।

### मिशन 41 हजार और मुक्त पहुंच

भारतीय रेल के ऊर्जा बिल को और कम करने के लिए रेलवे ने मुक्त पहुंच के माध्यम से बिजली खरीदना शुरू किया है और इस वर्ष बिजली संकषण बिल 2500 करोड़ रुपये कम होगा यानी 2014-15 के बिल की तुलना में वार्षिक आधार पर 25 प्रतिशत कम होगा। आप जानते हैं कि पहले का मिशन 41 हजार मुक्त पहुंच माध्यम से बिजली खरीद कर 2015-25 तक बिजली संकषण बिल में 41,000 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत के उद्देश्य से लांच किया गया था। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और सितंबर, 2017 तक हमने लगभग 5100 करोड़ रुपये की बचत की है यानी मिशन 41 हजार दस्तावेज के अनुमान से 1000 करोड़ रुपये अधिक।

### ऊर्जा लागत और कार्बन प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रेल में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

भारतीय रेल ने क्षेत्रीय रेल तथा उत्पादन इकाइयों में 2020-21 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 200 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। अभी तक 60 मेगावाट के सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। ये संयंत्र 270 स्टेशनों तथा 120 प्रशासकीय भवनों और अस्पतालों को कवर करते हैं। रेल भवनों की छतों पर 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के आदेश दिये गए हैं। भारतीय रेल 400 मेगावाट क्षमता स्थापना के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहा है ताकि भूमि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्रों से विभिन्न राज्यों से ऊर्जा संसाधन प्राप्त किया जा सके।

भारतीय रेल पीपीपी मॉडल के अंतर्गत छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का कार्य कर रहा है। इससे बिना किसी निवेश के ऊर्जा बिल में कमी आ रही है। इस मॉडल के अंतर्गत 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्रों के आदेश दिये गए हैं।

### ऊर्जा सक्षम उच्च अश्व शक्ति के इंजनों का उत्पादन

भारतीय रेल 200 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति क्षमता के साथ चलने वाली उच्च गति का यात्री इंजन विकसित करने के मार्ग पर है। उच्च गति के इंजन बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। आशा है कि मार्च, 2018 में सीएलडब्ल्यू द्वारा इसे लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल उच्च अश्व-शक्ति (9000 अश्व-शक्ति) का इंजन हासिल करने की योजना बना रहा है जो मध्यम उच्च गति संचालन (160 से 200 किलोमीटर प्रतिघंटे) के लिए चिन्हित मार्गों पर 200 किलोमीटर की रफ्तार पर भी रेल गाड़ी को रोक सकता है। वर्तमान 6000 अश्व शक्ति वाले मालगाड़ी इंजन तथा 9000 अश्व-शक्ति वाले सवारी गाड़ी इंजन को उन्नत बनाने की योजना है। सीएलडब्ल्यू में 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू कर दी गई है।

### सीधी बिजली सप्लाई (एचओजी)

भारतीय रेल ने सीधी बिजली सप्लाई प्रणाली प्रारंभ की है जिसमें इंजन ग्रिड से सीधे बिजली प्राप्त करेगा और कोच की लाइटिंग तथा एयरकंडिशनिंग तथा अन्य लोड को सीधी बिजली प्राप्त होगी। यह प्रणाली कोचों में बिजली सप्लाई करने वाले डीजल यान की आवश्यकता को समाप्त कर देगी और रेल गाड़ियां अतिरिक्त यात्री बोझ सहन कर सकेंगी। अभी 34 रेल गाड़ियां सीधी बिजली सप्लाई प्रणाली से चल रही हैं और इससे प्रतिवर्ष लगभग 87 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। चालू वित्त वर्ष में 64 रेलगाड़ियों में सीधी बिजली सप्लाई प्रणाली लगाई जाएगी।

### ईएमयू ट्रेन

नई बनने वाली ईएमयू रेलगाड़ियां ऊर्जा सक्षम होंगी और उनमें तीन फेस टेक्नॉलाजी के साथ उत्पादन क्षमता होगी।

ऊर्जा खपत को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम करते हुए भारतीय रेलवे 2016-17 से तीन फेस ऊर्जा सक्षम उत्पादन इंजन तथा ईएमयू को शामिल कर रहा है।

सम्मेलन में रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 5एमडब्ल्यूपीके सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, आनंद विहार तथा दिल्ली रेलवे स्टेशनों की छतों पर लगाया गया यह पहला सबसे बड़ा संयंत्र है।

यह परियोजना दिसंबर, 2016 में 4.14 रुपये प्रति यूनिट की उस समय की भारतीय रेल की सबसे कम कीमत पर पीपीपी मॉडल के अंतर्गत दी गई थी। यह संयंत्र 10 महीने के रिकार्ड अवधि में चालू हो गया। परियोजना की कुल लागत 37.45 करोड़ रुपये सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत डेवलपर द्वारा वहन की गई है और डेवलपर 25 वर्षों तक इसकी देखरेख करेगा तथा रेलवे 4.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खपत भुगतान करेगा। इसमें नेट मीटरिंग व्यवस्था भी उपलब्ध है जिसमें आवश्यकता से अधिक बिजली की आपूर्ति, बिजली वितरण कंपनियों को कर दी जाती है। इससे 421.4 लाख रुपये की बचत होगी और इन संयंत्रों की 30 प्रतिशत आवश्यकता पूरी होगी। इससे प्रतिवर्ष 6082 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आयेगी।

निम्नलिखित तकनीकी सत्र आयोजित किए गए –

1. थीम : हरित ऊर्जा परियोजनाएं – साझेदारी के लिए अवसर
2. थीम : भारतीय रेल के उच्च गति वाले इंजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति
3. थीम : ऊर्जा सक्षमता-प्रौद्योगिकी और समाधान
4. थीम : कार्बन प्रभाव कम करने की दिशा में रोडमैप
5. थीम : भारतीय रेल को 100 प्रतिशत बिजली संकषण की दिशा में ले जाना
6. थीम : जैव डीजल – प्रौद्योगिकी और समाधान

# TIME TO FINAL PREPARATION

LET'S START WITH MAHENDRAS



## FACILITIES FOR STUDENTS

- Exclusive Student Portal ([stportal.mahendras.org](http://stportal.mahendras.org))
- Up to Selection Facility.\* (For Selected Cards Only)
- Smart Lab
- Online Speed Test
- Written Speed Test (Detailed Result Analysis)
- Mahendras Class Assessment (MCA)
- Distribution of Class Worksheet (CWE)
- Study Material (English/Hindi)
- Student Bags (One at the time of Admission and another on qualifying PRE Exam or selection.)
- E-NEWSPAPER & MICA (Online & Offline)
- PSS/Online PSS/Online Videos
- Batch/Branch Transfer
- Batch Re-joining\* (For Selected Cards Only)
- Smart Class
- Star Performer Award (Monthly)
- Interview and GD PI Facility
- Counselling After Qualifying Pre Examination
- Alumni Facility (Many more Advantages)



**BANK**



**SSC**



**RAILWAY**



**STATE LEVEL EXAM**